are on the rise, warn doctors', published in "The Hindustan Times", dated 30th January, 1997;

(b) if so, the number of deaths occurred in the country because of air pollution during the last three years, year-wise and State-wise;

(c) whether ozone level is measured in India; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PROF. SAIFUDIN SOZ): (a) and (b) Yes, Sir. Owing to increase in levels of pullution in the ambient air due to large scale increase in vehicles and industrial complexes leading to atmospheric pullution, there could be an increase in health related problems. However, no conclusive statistical data is available on morbidity and mortality rates.

(c) Yes, Sir.

(d) Does not arise.

मध्य प्रदेश में वन भूमि पर हुए अतिक्रमणों का विनियमन

2934. **श्री नारायण प्रसाद गुप्ता:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने 24.10.80 तक वन भूमि पर हुए अतिक्रमणों का विनियमन करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार को प्रेषित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन प्रस्तावों को सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो स्वीकृति कब तक दी जाएगी?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़): (क) और (ख) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत मध्य प्रदेश सरकार से वन भूमि पर अवैध कब्जों के नियमितीकरण हेतु तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों की स्थिति नीचे दी गई है:

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	जिला	क्षेत्र (हेक्टेयर)	वर्तमान स्थिति
1.	मध्य प्रदेश	सभी जिले	1,03,000.00	राज्य सरकार ने 2.73 लाख हेक्टेयर वन भूमि के अंतरण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित उपयुक्तता मापदंड के आधार पर उपयुक्त पाए गए अवैध काबिजों के पक्ष में जुलाई, 1990 में 1.03 लाख हेक्टेयर वन भूमि के अंतरण का अनुमोदन किया गया था।
2.	मध्य प्रदेश	सभी जिले	1,77,938.431	राज्य सरकार से आवश्यक ब्यौरे मांगे गए और
3.	मध्य प्रदेश	खार गांव	3,773.349	इस मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय स्थल का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।

(ग) इस मंत्रालय में पूर्ण ब्यौरे और स्थल निरीक्षण की रिपोर्टें प्राप्त होने के पश्चात गुण दोष के आधार पर प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए शीघ्रता से कार्रवाई की जाएगी।

Scheme to create City Forest

2935. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) in how many States/Union Territories scheme to create city forest is being implemented;

(b) how much funds have been earmarked for this purpose;

(c) whether any such scheme is being implemented in Orissa; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PROF. SAIFUDDIN SOZ): (a) to (d) The informaiton is being collected and will be laid on the Table of the House.